



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 607]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 23, 2007/ज्येष्ठ 2, 1929

No. 607]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 23, 2007/JYAISTHA 2, 1929

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मई, 2007

का.आ. 801(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4 (4) के अनुसार, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रदीप नन्दाजोग की अध्यक्षता में गठित अधिकरण, जिसको विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 की धारा 4(1) के अंतर्गत यह न्याय निर्णय करने के लिए एक संदर्भ भेजा गया था कि क्या असम के नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) नामक संगठन को विधिविरुद्ध घोषित करने के पर्याप्त कारण हैं अथवा नहीं, का आदेश आम सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रदीप नन्दाजोग की अध्यक्षता में गठित विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण की रिपोर्ट।

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार ने दिनांक 23-11-2006 को अपनी अधिसूचना के तहत नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (जिसे इसमें इसके बाद 'एनडीएफबी' कहा गया है) को 'विधिविरुद्ध संगम' घोषित किया था।

भारत सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची कि एनडीएफबी इस आधार पर विधिविरुद्ध संगम है कि हिंसा छोड़ने पर सहमत होने के बावजूद, एनडीएफबी—

(i) पृथक बोडोलैंड के गठन के अपने उद्देश्यों को प्राप्त

करने में भारत की संप्रभुता तथा भू-भागीय अखंडता को विघटित करने वाले विभिन्न विधिविरुद्ध एवं हिंसक क्रियाकलापों में शामिल रहा है ;

(ii) इसने, पृथक बोडोलैंड का निर्माण करने के लिए स्वयं को यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम तथा नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (इसाक मुईवाह) जैसे अन्य विधिविरुद्ध संगमों के साथ स्वयं को मिला लिया है ;

(iii) अपने उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एनडीएफबी अनेक विधिविरुद्ध एवं हिंसक क्रियाकलापों में शामिल रहा, इस प्रकार इसने सरकार का प्राधिकार कम किया तथा लोगों में आतंक एवं दहशत फैलाई ;

(iv) पृथक बोडोलैंड के गठन की योजनाओं को वित्तपोषित तथा कार्यान्वित करने के लिए एनडीएफबी फिरौती हेतु अपहरण की कार्रवाइयों के अतिरिक्त व्यवसायियों, सरकारी कार्मिकों तथा अन्य नागरिकों से जबरन धन वसूली में शामिल रहा है ;

(v) अपने आतंकवादी एवं विद्रोही क्रियाकलापों को जारी रखने के उद्देश्य से नए काडरों की भर्ती के लिए सुनियोजित अभियान चलाना ;

(vi) गैर बोडो लोगों में दहशत और असुरक्षा की भावना उत्पन्न करने तथा उन्हें बोडो क्षेत्रों से चले जाने के लिए बाध्य करने के उद्देश्य से एनडीएफबी हत्याकांड और नृजातीय हिंसा में लगा हुआ है जिसके परिणामस्वरूप लोगों की हत्याएं तथा संपत्ति का विनाश हुआ है तथा असम में बोडो बहुल क्षेत्रों में रहने वाले हजारों गैर-बोडो लोगों को अपने निवास स्थल छोड़कर

जाना पड़ा है ;

- (vii) अपने अलगाववादी क्रियाकलापों को चलाने के लिए यह देश की सीमा पर शिविर तथा छिपने के अड्डे स्थापित कर रहा है ;
- (viii) एनडीएफबी एक पृथक बोडोलैण्ड राज्य के निर्माण के अपने संघर्ष में शस्त्र एवं अन्य सहायता प्राप्त करने के लिए अन्य देशों में सक्रिय भारत-विरोधी ताकतों से सहायता प्राप्त करता रहा है ।

भारत संघ ने यह नोट किया है कि एनडीएफबी की हिंसक गतिविधियों में निम्नलिखित गतिविधियां शामिल हैं :-

- (i) वर्ष 2004 में 58 हिंसक घटनाएं हुईं जिनमें एक सुरक्षा बल कार्मिक सहित 60 व्यक्तियों की मृत्यु हुई ;
- (ii) वर्ष 2005 में 21 हिंसक घटनाएं हुईं जिनमें 4 व्यक्ति मारे गए ;
- (iii) वर्ष 2006 (31 अगस्त, 2006 तक) में 15 हिंसक घटनाएं हुईं जिनमें 5 सुरक्षा बल कार्मिकों सहित 9 व्यक्ति मारे गए ।

उक्त आधारों पर तथा ऊपर नोट की गई गतिविधियों के आधार पर केन्द्र सरकार की यह राय थी कि एनडीएफबी के उपर्युक्त क्रियाकलाप भारत की संप्रभुता एवं अखंडता के लिए हानिकारक हैं तथा यदि एनडीएफबी की विधिविरुद्ध गतिविधियों को नियंत्रित नहीं किया गया तो यह पुनर्गठित होकर स्वयं को शस्त्रों से लैस करके नई भर्तियां करना शुरू कर देगी तथा हिंसक, आतंकवादी एवं अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होगी, धन संग्रहण करेगी तथा मासूम नागरिकों एवं सुरक्षा बल कर्मियों की जान के लिए खतरा उत्पन्न करेगी अतः इसे तत्काल प्रभाव से विधिविरुद्ध संगम घोषित करने के पर्याप्त कारण हैं ।

अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय ने दिनांक 19-12-2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 2120(अ) के द्वारा इस बात का न्याय निर्णय करने के प्रयोजन से इस अधिकरण का गठन किया कि क्या उक्त संगठन (एनडीएफबी) को तत्काल प्रभाव से विधिविरुद्ध संगम घोषित करने के पर्याप्त कारण हैं अथवा नहीं तथा गृह मंत्रालय ने अधिनियम की धारा 4 के उपबंध के अंतर्गत इस अधिकरण को एक संदर्भ भेजा था ।

इस अधिकरण को दिनांक 22-12-2006 को यह संदर्भ प्राप्त हुआ ।

दिनांक 22-11-2006 के आदेश के तहत संदर्भ प्राप्त होने पर इस अधिकरण ने इस संदर्भ पर प्रारंभिक सुनवाई 4-1-2007 के लिए तय की ।

इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 2 के उपबंध के अनुसरण में इस अधिकरण ने दिनांक 4-1-2007 के आदेश के द्वारा उक्त संगठन को नोटिस जारी करने का निदेश दिया था जिसमें इस नोटिस के तामील किए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर लिखित

में यह कारण बताने के लिए कहा गया था कि उक्त संगठन को विधिविरुद्ध संगठन क्यों न घोषित किया जाए । उक्त आदेश के तहत अधिकरण ने यह निदेश दिया था कि एनडीएफबी को नोटिस की तामिली उन 2 दैनिक राष्ट्रीय तथा दो स्थानीय समाचारपत्रों में प्रकाशन द्वारा की जाए जो उस स्थान पर परिचालित और प्रकाशित किए जाते हैं जहां एनडीएफबी की अपनी स्थापनाएं हैं अथवा असम राज्य तथा राज्य से बाहर इसकी उपस्थिति की जानकारी है तथा रेडियो, दूरदर्शन पर प्रसारण द्वारा और उद्घोषणा द्वारा उन क्षेत्रों में जहां एनडीएफबी के कार्यकलाप सामान्यतः किए जाते हैं, ढोल बजाकर अथवा मुनादी के द्वारा भी नोटिस की तामिली की जाए ।

इसके अतिरिक्त यह भी निदेश दिया गया कि नोटिस की तामिली प्रत्येक जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार के कार्यालय के नोटिस बोर्ड, जिला अथवा तहसील के मुख्यालय में, जैसा भी व्यवहार्य हो चिपकाकर भी की जाए ।

एनडीएफबी को दो सप्ताह के भीतर नोटिस की तामिली करने का निदेश दिया गया था । इसके बाद तामिली करने वाले संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के शपथपत्रों द्वारा समर्थित तामिली रिपोर्ट 2 सप्ताह के भीतर समर्थनकारी दस्तावेजों सहित दायर करने का निदेश दिया गया ।

आगे यह निदेश दिया गया कि अधिकरण का कार्यालय सामान्यतया नई दिल्ली में होगा, किंतु परिस्थितियों के अनुसार जब भी आवश्यक होगा, अधिकरण का कार्यालय असम राज्य अथवा किसी अन्य स्थान पर होगा ।

सेवा शपथपत्र श्री ए. के. गोयल, निदेशक भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दाखिल किया गया था सेवा शपथपत्र में यह उल्लेख किया गया था कि इस अधिकरण द्वारा दिनांक 4-1-2007 को पारित किए गए आदेश के अनुसरण में, भारत सरकार द्वारा मुख्य सचिव, असम सरकार को नोटिस की तामिली करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने हेतु दिनांक 6-1-2007 का नोटिस अग्रेषित किया गया था । शपथपत्र में यह उल्लेख किया गया था कि असम सरकार ने नोटिस की प्रभावी तामिली करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए :

- (i) यह नोटिस अनुलग्नक I से IV के अनुसार चार स्थानीय समाचार पत्रों अर्थात् दिनांक 19-1-2007 के 'द अमर असोम', दिनांक 19-1-2007 के 'द असम ट्रिब्यून', दिनांक 21-1-2007 के 'दैनिक जागरण' तथा दिनांक 22-1-2007 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित किया गया था ।
- (ii) असम सरकार के अनुसार, अनुलग्नक-V के अनुसार यह नोटिस दूरदर्शन केंद्र, गुवाहाटी से प्रकाशित किया गया था ।
- (iii) असम सरकार के अनुसार, यह नोटिस अनुलग्नक-VI के अनुसार आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से दिनांक 1-2-2007 को रीजनल न्यूज बुलेटिन में प्रसारित किया गया था ।

(iv) असम सरकार के अनुसार, एनडीएफबी पर प्रतिबंध लगाने का समाचार अनुलग्नक-VIII के अनुसार दिनांक 23-1-2007 को सांय 7.00 बजे दूरदर्शन केंद्र, गुवाहाटी के माध्यम से असमी बुलेटिन में प्रसारित किया गया था।

(v) इस नोटिस को अनुलग्नक-VIII के अनुसार असम राज्य के 13 जिलों में स्पष्ट स्थानों पर सार्वजनिक रूप से लगाया गया एवं तामील की गई।

सेवा शपथपत्र श्री एस. के. रॉय, संयुक्त सचिव, असम सरकार, राजनैतिक (क) विभाग, असम सचिवालय, दिसपुर, गुवाहाटी द्वारा भी दाखिल किया गया था जिसमें यह बताया गया था कि यह नोटिस दिनांक 22-1-2007 के राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार-पत्र "इंडियन एक्सप्रेस", दिनांक 22-1-2007 के राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र 'दैनिक जागरण', दिनांक 19-1-2007 के देशी भाषा के असमी समाचार पत्र 'अमर असोम' तथा 19-1-2007 के स्थानीय अंग्रेजी समाचार-पत्र 'असम ट्रिब्यून' में प्रकाशित किया गया था। नोटिस की विषय वस्तु को दिनांक 1-2-2007 को आकाशवाणी, गुवाहाटी में रात्रि समय 9.25 पर क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन में शामिल किया गया था। दूरदर्शन केंद्र, गुवाहाटी ने नोटिस की विषय वस्तु को 23-1-2003 को सांय 7.00 बजे के क्षेत्रीय असमी समाचार बुलेटिन में प्रसारित किया। इस नोटिस की तामील स्पष्ट स्थानों/हाटों/बाजारों में नगाडा बजाकर/लाउडस्पीकों द्वारा घोषणा करके, जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार के कार्यालय तथा थाने में नोटिस चिपकाकर भी की गई तथा इसे एनडीएफबी के जाने पहचाने कार्यकर्ताओं के परिवार के सदस्यों को स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में दिया गया तथा असम के विभिन्न जिलों में यह कार्य किया गया जहां विधिविरुद्ध संगठन (एनडीएफबी) अपने कार्यकलाप कर रहा है।

अधिकरण द्वारा 28-2-2007 को की गई सुनवाई में, दाखिल किए गए शपथपत्रों का अवलोकन करने पर, अधिकरण संतुष्ट हो गया कि दिनांक 4-1-2007 के आदेश का तामील करने के लिए तय किए गए समय के भीतर आदेशों का अनुपालन कर लिया गया है। यह माना गया कि एनडीएफबी को भलीभांति नोटिस की तामील कर दी गई है। यह नोट किया कि दिए गए समय अर्थात् नोटिस होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर एनडीएफबी द्वारा कोई आपत्ति/उत्तर लिखित बयान दायर नहीं किया गया है। यह भी नोट किया गया कि एनडीएफबी की ओर से व्यक्तिगत रूप से अथवा वकील के माध्यम से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः, अधिकरण ने निदेश दिया कि आगे की जांच एक तरफा की जाए।

अतः, एनडीएफबी को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) नियम 1968 के नियम 6 के तहत दिए गए अधिकरण के निदेशों के अनुसार विधिवत नोटिस की तामील की गई थी और उसने अधिकरण द्वारा संचालित कार्यवाहियों में भाग लेना पसंद नहीं किया।

असम सरकार ने निम्नलिखित अधिकारियों के दस्तावेजों सहित दिए गए शपथपत्रों द्वारा साक्ष्य इकट्ठे किए :-

(1) श्री एस. के. रॉय, पुत्र श्री एस. एस. रॉय, संयुक्त सचिव, असम सरकार गृह एवं राजनैतिक विभाग,

असम सचिवालय, दिसपुर, गुवाहाटी।

- (2) श्री अरविंद कलिता, पुत्र श्री मतिराम कलिता, निवासी दिसपुर, गुवाहाटी पुलिस अधीक्षक, विशेष ऑपरेशन यूनिट, विशेष शाखा, असम, काहिलीपारा, गुवाहाटी।
- (3) श्री देबराज उपाध्याय, एपीएस, पुलिस अधीक्षक, जिला बारपेटा।
- (4) श्री अभिजीत बोरा, एपीएस, पुलिस अधीक्षक, जिला गोलपारा।
- (5) श्री के. जे. सैकिया, एपीएस, पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत जिला बक्सा।
- (6) श्री प्रदीप पुजारी, एपीएस, पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत, जिला चिरांग।
- (7) श्री अनुराग तंखा, आईपीएस, पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत, जिला कर्बी आंगलोंग, डिफू।
- (8) श्री हिरेन चन्द्र नाथ, आईपीएस, पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत, जिला कोकराझार।
- (9) श्री पार्थ सारथी महंत, एपीएस, पुलिस अधीक्षक, जिला धुबरी।
- (10) श्री पंकज शर्मा, एपीएस, पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत, जिला उडालगुरी।
- (11) श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह, आईपीएस, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत, सिटी गुवाहाटी।
- (12) श्री एम. पी. गुप्ता, आईपीएस, पुलिस अधीक्षक, जिला सोनितपुर, असम।

भारत सरकार ने साक्ष्य प्राप्त करने के लिए और 2 सप्ताह की अवधि का समय मांगा तदनुसार समय प्रदान कर दिया गया।

अधिकरण ने 4-4-2007 को शिलांग में होटल पाईनवुड में सुनवाई की। श्री एस. के. रॉय, संयुक्त सचिव, असम सरकार, गृह एवं राजनीति विभाग, दिसपुर, गुवाहाटी ने दैनिक समाचार पत्रों अर्थात्, दिनांक 2-4-2007 का 'द इंडियन एक्सप्रेस', दिनांक 1-4-2007 का 'द असम ट्रिब्यून', गुवाहाटी, दिनांक 1-4-2007 का 'दैनिक जागरण', दिनांक 1-4-2007 का 'बोडोसा' (बोडो भाषा का दैनिक समाचार पत्र), दिनांक 2-4-2007 का 'सनसेयरी बोडो लैंड इंगखोंग : बिजनी', दिनांक 2-4-2007 का 'असोमिया खोबर' तथा दिनांक 2-4-2007 का 'आजी' के उद्धरण रिकार्ड में प्रस्तुत किए जिसमें इस सार्वजनिक सूचना का साक्ष्य था कि अधिकरण 4, 5 तथा 7 अप्रैल, 2007 की रात 10.30 बजे शिलांग में सुनवाई करेगा।

4, 5 एवं 7 अप्रैल, 2007 को शिलांग में सुनवाई के दौरान किसी ने भी एनडीएफबी का प्रतिनिधित्व नहीं किया। किसी नागरिक ने उक्त तारीखों पर पुछताछ में हिस्सा नहीं लिया।

भारत सरकार ने श्री आर.आर.झा, निदेशक, भारत सरकार, गृह मंत्रालय के साक्ष्य द्वारा एक शपथपत्र दाखिल किया तथा शपथपत्र

के साथ समर्थन के लिए दस्तावेज साथ थे।

पी डब्ल्यू-1, श्री एस.के. राय, संयुक्त सचिव, असम सरकार, गृह एवं राजनैतिक विभाग (दिसपुर), गुवाहाटी द्वारा दायर शपथपत्र पी-1 के अनुसार, 22-11-2004 से 22-11-2006 तक एनडीएफबी द्वारा की गई घटनाओं का विवरण चार्ट ई एक्स. पी डब्ल्यू-1/3 में सूचीबद्ध किया गया था। उक्त प्रदर्श में संकलित आंकड़े असम राज्य में 13 प्रशासनिक जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार थे। गवाह ने यह प्रमाणित किया कि गतिविधियों के निलंबन संबंधी करार पर एनडीएफबी, असम सरकार तथा भारत सरकार के बीच 24-5-2005 को हस्ताक्षर किए गए। उन्होंने ई एक्स. पी डब्ल्यू-1/2(1) के रूप में उक्त करार को प्रमाणित किया। एनडीएफबी की ओर से इस करार पर बी. स्वमखर उर्फ गोविन्द बसुमतारी द्वारा हस्ताक्षर किए गए। उन्होंने 27-5-2006 के करार ई एक्स. पी. डब्ल्यू-1/2 (2), जिसके द्वारा पूर्व करार ई एक्स.पी. डब्ल्यू-1/2 (1) को आगामी छह माह की अवधि तक बढ़ाया गया था, को प्रमाणित किया। उन्होंने अभियान के निलंबन संबंधी प्रारंभिक करार को 1-12-2006 के बाद आगामी छह माह की अवधि तक बढ़ाए जाने संबंधी दिनांक 28-11-2006 के करार ई. एक्स. पी डब्ल्यू-1/2 (3) को भी प्रमाणित किया।

गवाह ने बताया कि शांति प्रक्रिया तथा एनडीएफबी के साथ राजनैतिक वार्ता से कोई सार्थक प्रगति नहीं हो रही थी क्योंकि एनडीएफबी ने, ई. एक्स. पी डब्ल्यू-1/2 (1) में परिकल्पित सरकार ने विचारार्थ मांगों का चार्टर प्रस्तुत नहीं किया था। गवाह ने बताया कि आसूचना रिपोर्टों से यह पता चलता है कि एनडीएफबी के कट्टर सदस्य सक्रिय रूप से विदेशी भू-भागों में स्थापित आई एस आई तथा अन्य उग्रवादी संगठनों जैसे प्रतिबंधित संगठनों के सम्पर्क में थे। उन्होंने ई. एक्स. पी डब्ल्यू-1/4 (1), ई. एक्स. पी डब्ल्यू-1/4 (2), ई. एक्स. पी डब्ल्यू-1/5 (1), ई. एक्स. पी डब्ल्यू-1/5 (2) तथा ई. एक्स. पी डब्ल्यू-1/6 (2) को भी प्रमाणित किया जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि एनडीएफबी का काडर अन्य प्रतिबंधित संगठनों, आईएसआई तथा विदेशी भू भागों में स्थापित उग्रवादी संगठनों के साथ बातचीत कर रहा था। उन्होंने बताया कि ई. एक्स. पी डब्ल्यू-1/3 में उल्लिखित जबरन धन वसूली, अपहरण तथा हत्या की घटनाएं मुख्यतः असम राज्य में गैर-बोरो नागरिक के विरुद्ध की जाती हैं।

पी डब्ल्यू-2, श्री अरविन्द कलिता, पुलिस अधीक्षक (एसओयू), विशेष शाखा, असम कहिलीपारा, गुवाहाटी ने बयान दिया कि दिनांक 9-2-2007 का शपथपत्र, पी-2 उनके द्वारा दायर किया गया था। उन्होंने बताया कि ई एक्स. पी डब्ल्यू-1/4 (1), ई. एक्स. पी. डब्ल्यू-1/4 (2), ई. एक्स. पी डब्ल्यू-1/4 (3), ई. एक्स. पी डब्ल्यू-1/5(1), ई. एक्स. पी डब्ल्यू-1/5 (2) ई. एक्स. पी डब्ल्यू-1/4 (3) ई. एक्स. पी डब्ल्यू-1/6 (1) और ई. एक्स. पी डब्ल्यू-1/6 (2) एनडीएफबी के पदाधिकारी बेनू बोरो सोहितन नर्जरी तथा गोविन्द बासुमतारी के डब्लिफिंग बयानों के उद्धरण थे। उन्होंने बताया कि असम सरकार, गृह एवं राजनैतिक विभाग को उक्त उद्धरण उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए तथा ये पी डब्ल्यू-1 के शपथपत्र के साथ दायर किए गए। उन्होंने यह भी बताया कि ई एक्स. पी डब्ल्यू-1/8 (1), ई. एक्स. पी डब्ल्यू-1/8 (2), ई. एक्स. पी डब्ल्यू-1/8 (3), ई. एक्स. पी डब्ल्यू-1/8 (4), ई. एक्स. पी

डब्ल्यू-1/8 (5) तथा ई. एक्स. पी डब्ल्यू-1/8 (6) उन्हें संबंधित पुलिस थानों के पुलिस अधिकारियों द्वारा मुहैया कराए गए थे तथा यह कि उन्होंने ये असम सरकार, गृह एवं राजनैतिक विभाग को भेज दिए। उन्होंने यह भी बताया कि पी डब्ल्यू-1 को ई. एक्स. पी डब्ल्यू-1/9 (1), ई. एक्स. पी डब्ल्यू-1/9 (2) तथा ई. एक्स. पी डब्ल्यू-1/9 (3) उनके कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए।

गवाह ने उक्त सभी दस्तावेजों को मूल रूप में प्रस्तुत किया।

उन्होंने यह भी बताया कि आसूचना रिपोर्टों के अनुसार, रंजन डैमरी नामक एक व्यक्ति वर्तमान में एनडीएफबी का अध्यक्ष बना हुआ है तथा वह बंगलादेश में है। उन्होंने बताया कि आसूचना रिपोर्टों से यह पता चलता है कि एनडीएफबी के बंगलादेश में चिटगांव हिल्स में रंगमती, बल्सोरी तथा मोनिकुरा 3 स्थानों पर शिविर हैं। उन्होंने यह भी बताया कि आसूचना रिपोर्टों से यह पता चलता है कि एनडीएफबी काडर एनएससीएन (आईएम), एनएलएफटी, पीएलए (मणिपुर), उल्फा, एनएनबीसी, एचएनएलसी तथा आईएसआई एवं डीजीएफआई जैसे अन्य अलगाववादी/आतंकवादी संगठनों के संपर्क में हैं। (उन्होंने यह भी बताया कि आसूचना रिपोर्टों से यह पता चलता है कि एनडीएफबी अरकन म्यांमार तथा खीमेर की अध्यक्षता में चलाए जा रहे भूमिगत आंदोलन के संपर्क में था। गवाह ने पी डब्ल्यू-1 का समर्थन किया कि ई. एक्स. पी डब्ल्यू-1/3 में उल्लिखित अपहरण, जबरन धन वसूली तथा हत्या की घटनाएं मुख्यतः असम राज्य में गैर-बोरो नागरिकों के विरुद्ध थीं।

पी डब्ल्यू-3, श्री देबराज उपाध्याय, पुलिस अधीक्षक, बारपेटा जिला, असम ने बताया कि दिनांक 8-2-2007 का शपथ पत्र पी-3 उनके द्वारा दायर किया गया था। उन्होंने ई. एक्स. पी डब्ल्यू-3/1, ई. एक्स. पी डब्ल्यू-3/2 (1) से ई. एक्स. पी डब्ल्यू-3/2 (4) तक, ई. एक्स. पी डब्ल्यू-3/3 (1) से ई. एक्स. पी डब्ल्यू-3/3 (3) तक, ई. एक्स. पी डब्ल्यू-3/4 (1), ई. एक्स. पी डब्ल्यू-3/5, ई. एक्स. पी डब्ल्यू-3/6 (1) से ई. एक्स. पी डब्ल्यू-3/6 (3), ई. एक्स. पी डब्ल्यू-3/7, ई. एक्स. पी डब्ल्यू-3/8, ई. एक्स. पी डब्ल्यू-3/9 (1) से ई. एक्स. पी डब्ल्यू-3/9 (3) और ई. एक्स. पी डब्ल्यू-3/10 दस्तावेजों को प्रमाणित किया। मूल दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। उक्त दस्तावेजों से यह सिद्ध होता है कि 5-4-2005 को पुलिस थाना सोरभोग में यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एनडीएफबी काडर जबरन धन वसूली के अभियान में लिप्त था। सीआरपीएफ की 93 बटालियन के साथ एक पुलिस दल हेलोसिगुड़ी, ओडलगुड़ी, मैनमता, नबडंगुड़ी तथा समथेबारी गया। स्थानीय जांच से यह ज्ञात हुआ कि अभियुक्तों ने उक्त क्षेत्रों में असम के नागरिकों से जबरन धन वसूली की।

ई एक्स. पी डब्ल्यू-3/1 से ई एक्स. पी डब्ल्यू-3/10 तक प्रभावित क्षेत्रों में लोगों द्वारा सौंपी गई जीडी प्रविष्टियों, जबरन धन वसूली के नोटिसों, जब्ती ज्ञापनों, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज किए गए व्यक्तियों के ऐसे बयानों की प्रतियां थीं कि एनडीएफबी काडर उन्हें शारीरिक नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर उन्हें तथा अन्य व्यक्तियों को धन देने के लिए धमकी दे रहे हैं।

पी डब्ल्यू-4, श्री अभिजीत बोरा, पुलिस अधीक्षक, गोलपाड़ा जिला, असम ने बताया कि दिनांक 6-2-2007 का शपथपत्र पी-4 उनके द्वारा दायर किया गया था। उन्होंने ई एक्स. पी डब्ल्यू-4/1, ई एक्स. पी डब्ल्यू-4/2, ई एक्स. पी डब्ल्यू-4/3 (1), ई एक्स. पी डब्ल्यू-4/3(2) तथा ई एक्स. पी डब्ल्यू-4/4 को प्रमाणित किया

द्वारा जबरन धन वसूली के साक्ष्य संबंधी दस्तावेज, ई एक्स. पी डब्ल्यू-4/1 से ई एक्स. पी डब्ल्यू-4/4, कुर्की ज्ञापनों से इस क्षेत्र में एनडीएफबी का डार द्वारा नागरिकों को जारी किए गए जबरन धन वसूली से संबंधित पत्रों की जानकारी मिली। ई एक्स. पी डब्ल्यू-4/4, कैप्टन वी.के. सर्मा का इस आशय का बयान है कि उन्होंने किसी लखन सिंह ब्रह्मा को पकड़ा जिसके पास एनडीएफबी के पत्र शीशों पर लिखे जबरन धन वसूली से संबंधित पत्र थे। ई एक्स. पी डब्ल्यू-4/4(1), ई एक्स. पी डब्ल्यू-4/4(2), ई एक्स. पी डब्ल्यू-4/4(3), ई एक्स. पी डब्ल्यू-4/4(4), ई एक्स. पी डब्ल्यू-4/4(5), ई एक्स. पी डब्ल्यू-4/4(6), ई एक्स. पी डब्ल्यू-4/4(7), ई एक्स. पी डब्ल्यू-4/4(8), ई एक्स. पी डब्ल्यू-4/4(9), ई एक्स. पी डब्ल्यू-4/4(10), ई एक्स. पी डब्ल्यू-4/4(11) और ई एक्स. पी डब्ल्यू-4/4(12) विभिन्न व्यक्तियों के बयान हैं जिन्हें जबरन धन वसूली के संबंध में पत्र जारी किए गए तथा जिन्होंने उस क्षेत्र में दुकानदारों से धन उगाहने वाले बोरो युवाओं की गिरफ्तारी की गवाही दी थी।

पी डब्ल्यू-5, श्री कंगकन ज्योति सैकिया, पुलिस अधीक्षक, बक्सा जिला, असम ने बताया कि दिनांक 7-2-2007 का शपथ पत्र पी-5 उनके द्वारा दायर किया गया। उन्होंने ई एक्स. पी डब्ल्यू-5/1, ई एक्स. पी डब्ल्यू-5/2(1), ई एक्स. पी डब्ल्यू-5/3(1) से ई एक्स. पी डब्ल्यू-5/3(5) तक, ई एक्स. पी डब्ल्यू-5/4, ई एक्स. पी डब्ल्यू-5/5, ई एक्स. पी डब्ल्यू-5/6 (1), से ई एक्स. पी डब्ल्यू-5/6(3), ई एक्स. पी डब्ल्यू-5/7, ई एक्स. पी डब्ल्यू-5/8, ई एक्स. पी डब्ल्यू-5/9, ई एक्स. पी डब्ल्यू-5/10, ई एक्स. पी डब्ल्यू-5/11(1) तथा ई एक्स. पी डब्ल्यू-5/11(2) को प्रमाणित किया। मूल दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। उक्त दस्तावेजों में डी डी एंटी, एफआईआर तथा गवाहों के बयान शामिल हैं तथा ये एनडीएफबी कांडर द्वारा जबरन धन वसूली की धमकी से संबंधित हैं। ई एक्स. पी डब्ल्यू-5/9 कैप्टन आशीष पाण्डे, 16, गढ़वाल रायफल्स का इस आशय का बयान है कि उन्होंने किसी रंजीत गुयान तथा बेदमगथा बसुमात्री को दारंगा मेला बाजार से उस समय पकड़ा था जब वे दुकानदारों को शारीरिक नुकसान की धमकी देकर धन की वसूली कर रहे थे। ई एक्स. पी डब्ल्यू-5/9 रिकवरी मेमो है जिससे उक्त 2 व्यक्तियों से भारतीय मुद्रा और भूटानी मुद्रा की वसूली का पता चलता है। गवाह ने यह भी बताया कि उसके जिले में पिछले दो वर्षों में एनडीएफबी संवर्ग के पैंतीस सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था। उसने बताया कि उसके जिले में जबरन धन वसूली की घटनाएं मुख्यतः असम राज्य में गैर-बोडो नागरिकों के विरुद्ध हैं।

पी डब्ल्यू-6, श्री प्रदीप पुजारी, पुलिस अधीक्षक, चिरंग जिला, असम ने बताया कि दिनांक 6-2-2007 का पी-6 उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उसने ई एक्स. पी डब्ल्यू-6/1, ई एक्स. पी डब्ल्यू-6/2, ई एक्स. पी डब्ल्यू-6/3(1), ई एक्स. पी डब्ल्यू-6/3(2), ई एक्स. पी डब्ल्यू-6/4(1), ई एक्स. पी डब्ल्यू-6/4(2), ई एक्स. पी डब्ल्यू-6/5, ई एक्स. पी डब्ल्यू-6/6, ई एक्स. पी डब्ल्यू-6/7(1), ई एक्स. पी डब्ल्यू-6/8(1) से ई एक्स. पी डब्ल्यू-6/8(5), ई एक्स. पी डब्ल्यू-6/9, ई एक्स. पी डब्ल्यू-6/10, ई एक्स. पी डब्ल्यू-6/11(1), ई एक्स. पी डब्ल्यू-6/11(2), ई एक्स. पी डब्ल्यू-6/12, ई एक्स. पी डब्ल्यू-6/13(1) से ई एक्स. पी डब्ल्यू-6/13(5), ई एक्स. पी

डब्ल्यू-6/14(1), ई एक्स. पी डब्ल्यू-6/14(2), ई एक्स. पी डब्ल्यू-6/15, ई एक्स. पी डब्ल्यू-6/16 (1) से ई एक्स. पी डब्ल्यू-6/16(3), ई एक्स. पी डब्ल्यू-6/17(1), ई एक्स. पी डब्ल्यू-6/17(2), ई एक्स. पी डब्ल्यू-6/18(1) से ई एक्स. पी डब्ल्यू-6/18(3), ई एक्स. पी डब्ल्यू-6/19(1) से ई एक्स. पी डब्ल्यू-6/19(4), ई एक्स. पी डब्ल्यू-6/20(1), ई एक्स. पी डब्ल्यू-6/20(2), ई एक्स. पी डब्ल्यू-6/21(1) से ई एक्स. पी डब्ल्यू-6/21(3) एवं ई एक्स. पी डब्ल्यू-6/22 को साबित किया। मूल दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। उक्त दस्तावेज 'रिकवरी मेमो', बरामदगी सूचियां और बयान हैं जो न केवल गवाहों के बल्कि एनडीएफबी संवर्ग के सदस्यों अर्थात् रंजीत गोयारी और अंत राज चेटरी के द्वारा दिए गए हैं। गिरफ्तार किए गए संवर्गों के बयानों का आशय यह है कि उन्हें एनडीएफबी में शामिल होने के लिए बहकाया गया था और भूटान तथा सेंकरी में शिविरों में प्रशिक्षण लेने के बाद उन्हें एनडीएफबी कार्यकर्ताओं को वित्तपोषित करने के लिए धन राशि इकट्ठा करने का कार्य सौंपा गया था। बयानों से यह पता चलता है कि एनडीएफबी ने रोसन बसुमतारी को क्षेत्र में प्लाटून कमांडर के रूप में नामित किया गया था। वह एनडीएफ बी संवर्ग क्षेत्र में ट्रक ड्राइवर्स से जबरन धन वसूली करता था। बयानों से क्षेत्र में कार्यरत एनडीएफबी के अन्य सदस्यों के नामों का पता चलता है प्रभावित नागरिकों के बयानों से यह पता चलता है कि शारीरिक हिंसा की धमकी देकर उन्हें एनडीएफबी संवर्ग को धन देने के लिए बाध्य किया जा रहा था। 'रिकवरी मेमो' से चिरांग जिले में नागरिकों को एनडीएफबी संवर्ग द्वारा जबरन धन वसूली के पात्रों का साक्ष्य मिला।

पीडब्ल्यू-6 ने 10-4-2007 को एक अतिरिक्त शपथ-पत्र दाखिल किया जिससे ई एक्स. पी डब्ल्यू-6-11(1), ई एक्स. पी डब्ल्यू-6/11(2), ई एक्स. पी डब्ल्यू-6/12, ई एक्स. पी डब्ल्यू-6/13(1), ई एक्स. पी डब्ल्यू-6/13(2), ई एक्स. पी डब्ल्यू-6/13(3), ई एक्स. पी डब्ल्यू-6/13(4), ई एक्स. पी डब्ल्यू-6/13(5), ई एक्स. पी डब्ल्यू-6/14(1), ई एक्स. पी डब्ल्यू-6/14(2), ई एक्स. पी डब्ल्यू-6/15, ई एक्स. पी डब्ल्यू-6/16(1), ई एक्स. पी डब्ल्यू-6/16(2), ई एक्स. पी डब्ल्यू-6/16(3), ई एक्स. पी डब्ल्यू-6/17(1) ई एक्स. पी डब्ल्यू-6/17(2), ई एक्स. पी डब्ल्यू-6/18(1), ई एक्स. पी डब्ल्यू-6/18(2), ई एक्स. पी डब्ल्यू-6/18(3), ई एक्स. पी डब्ल्यू-6/19(1), ई एक्स. पी डब्ल्यू-6/19(1-क), ई एक्स. पी डब्ल्यू-6/19(2), ई एक्स. पी डब्ल्यू-6/19(2क), ई एक्स. पी डब्ल्यू-6/19(3), ई एक्स. पी डब्ल्यू-6/19(3क-1), ई एक्स. पी डब्ल्यू-6/19(3क-2), ई एक्स. पी डब्ल्यू-6/19(4), ई एक्स. पी डब्ल्यू-6/19(4क), ई एक्स. पी डब्ल्यू-6/20(1), ई एक्स. पी डब्ल्यू-6/20(2), ई एक्स. पी डब्ल्यू-6/21(1), ई एक्स. पी डब्ल्यू-6/21(1क-1), ई एक्स. पी डब्ल्यू-6/21(1क-2), ई एक्स. पी डब्ल्यू-6/21(2), ई एक्स. पी डब्ल्यू-6/21(2क-1), ई एक्स. पी डब्ल्यू-6/21(2क-2), ई एक्स. पी डब्ल्यू-6/21(3) और ई एक्स. पी डब्ल्यू-6/22 साबित होते हैं। उक्त दस्तावेजों से 3-2-2005 को एनडीएफबी के उग्रवादियों और सेना के बीच मुकाबले और उग्रवादी से प्रभावित वसूली की बात साबित होती है। दस्तावेजों से 30-11-2004 को एनडीएफबी के उग्रवादियों और सेना के बीच मुकाबले और एक

को एनडीएफबी के उग्रवादियों और सेना के बीच मुकाबले और एक ए.के.-47 राइफल सहित हथियारों एवं गोलाबारूद की बरामदगी की बात साबित होती है।

पी डब्ल्यू-7, श्री अलगुग तनखा, पुलिस अधीक्षक, कार्बी आंगलांग ने यह बयान दिया कि 7-2-2002 का शपथ-पत्र पी-7 उसके द्वारा दिया गया था। उन्होंने दस्तावेज ई एक्स. पी डब्ल्यू-7/1, ई एक्स. पी डब्ल्यू-7/2(1), ई एक्स. पी डब्ल्यू-7/2(2), ई एक्स. पी डब्ल्यू-7/3, ई एक्स. पी डब्ल्यू-7/4 (1), से ई एक्स. पी डब्ल्यू-7/4(3), ई एक्स. पी डब्ल्यू-7/5, ई एक्स. पी डब्ल्यू-7/6(1), ई एक्स. पी डब्ल्यू-7/6(2), ई एक्स. पी डब्ल्यू-7/7, ई एक्स. पी डब्ल्यू-7/8(1) से ई एक्स. पी डब्ल्यू-7/8(4), ई एक्स. पी डब्ल्यू-7/9(1), ई एक्स. पी डब्ल्यू-7/9(2), ई एक्स. पी डब्ल्यू-7/10, ई एक्स. पी डब्ल्यू-7/11(1), ई एक्स. पी डब्ल्यू-7/11(2), ई एक्स. पी डब्ल्यू-7/12(1) और ई एक्स. पी डब्ल्यू-7/12(2) को साबित किया। मूल दस्तावेजों को देखने के बाद लौटा दिया गया। उक्त दस्तावेज 'रिकवरी मेमो', गवाहों के बयान, एनडीएफबी संवर्ग के एक सदस्य भरत बोडो का इकबालिया बयान जिसमें उसने संवर्ग के अन्य सदस्यों के नाम बताए हैं; एक अन्य एनडीएफबी कार्यकर्ता श्री संतोष का इकबालिया बयान है। जब्ती सूची में जबरन धन-वसूली के पत्रों, हथियारों एवं गोलाबारूद की बरामदगी का पता चलता है, ई एक्स. पी डब्ल्यू-7/8(1) में हथगोलों, 9 एमएम खाली करतूसों, मोबाइल फोनों की बरामदगी का साक्ष्य है।

पी डब्ल्यू-8, श्री हीरेन चन्द्र नाथ, पुलिस अधीक्षक, कोकराझार जिला, असम ने बयान दिया कि 9-2-2007 का शपथ पत्र पी-8 उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने दस्तावेज ई एक्स. पी डब्ल्यू-8/1, ई एक्स. पी डब्ल्यू-8/2, ई एक्स. पी डब्ल्यू-8/3(1) से ई एक्स. पी डब्ल्यू-8/3(8), ई एक्स. पी डब्ल्यू-8/4, ई एक्स. पी डब्ल्यू-8/5, ई एक्स. पी डब्ल्यू-8/6(1) से ई एक्स. पी डब्ल्यू-8/6(8), ई एक्स. पी डब्ल्यू-8/7, ई एक्स. पी डब्ल्यू-8/8, ई एक्स. पी डब्ल्यू-8/9, ई एक्स. पी डब्ल्यू-8/10, ई एक्स. पी डब्ल्यू-8/10(1) से ई एक्स. पी डब्ल्यू-8/10(8), ई एक्स. पी डब्ल्यू-8/11, ई एक्स. पी डब्ल्यू-8/12, ई एक्स. पी डब्ल्यू-8/13 और ई एक्स. पी डब्ल्यू-8/13(1), ई एक्स. पी डब्ल्यू-8/13(13) को साबित किया। उन्होंने बताया कि उनके जिले में जबरन धन-वसूली, अपहरण और हत्या की घटनाएँ मुख्यतः असम राज्य में गैर-बोडो नागरिकों के विरुद्ध हैं। गवाहों द्वारा साबित दस्तावेज एफआईआर, जब्ती ज्ञापन, शिकायतों के विवरण, एनडीएफबी के सदस्यों द्वारा मारे गए व्यक्तियों के शवों की पहचान, संबंधियों का यह बयान कि एनडीएफबी के सदस्य मारे गए लोगों से संरक्षण राशि की मांग कर रहे थे, हथियारों और गोलाबारूद से संबंधित वसूली ज्ञापन, एनडीएफबी संवर्ग के सदस्यों द्वारा की गई जबरन धन-वसूली के विवरण को स्पष्ट करने वाली डायरी रिकार्डिंग और एनडीएफबी संवर्ग के गिरफ्तार सदस्यों के स्वेच्छा से दिए गए बयान हैं। ई एक्स. पी डब्ल्यू-8/7 से 28-1-2005 को 11वीं जे एण्ड के लाइट इन्फैंट्री के अधिकारियों पर घात लगाकर किए गए हमले की घटना का और मोहन बसुमतारी, एनडीएफबी का एक हथियारबंद उग्रवादी जो पीछा करने के बाद गिरफ्तार किया गया था, से हथियारों और गोलाबारूद की बरामदगी का पता चलता है।

पीडब्ल्यू-9 श्री पार्थ सारथी महन्ता, पुलिस अधीक्षक, धुबरी, असम ने बयान दिया कि 6-2-2007 का शपथ पत्र पी-9 उनके द्वारा

प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने ई एक्स. पी डब्ल्यू-9/1, ई एक्स. पी डब्ल्यू-9/2, ई एक्स. पी डब्ल्यू-9/3(1) से ई एक्स. पी डब्ल्यू-9/3(6), ई एक्स. पी डब्ल्यू-9/4(1) से ई एक्स. पी डब्ल्यू-9/4(3), ई एक्स. पी डब्ल्यू-9/5(1), ई एक्स. पी डब्ल्यू-9/5(2), ई एक्स. पी डब्ल्यू-9/5(3) से ई एक्स. पी डब्ल्यू-9/5(4), ई एक्स. पी डब्ल्यू-9/6(1) से ई एक्स. पी डब्ल्यू-9/6(4) को साबित किया। मूल दस्तावेज देखे गए और लौटा दिए गए। दस्तावेजों से एनडीएफबी संवर्ग के सदस्यों द्वारा जबरन न-वसूली और हिंसक घटनाओं का पता चलता है जिनके परिणामस्वरूप बाजार में संयोग से पुलिस की मौजूदगी के कारण मौत हुई जहाँ स्थानीय दुकानदारों को धमकाया जा रहा था। दस्तावेजों से, जबरन धन-वसूली करने वाले मृतकों के संबंधियों के बयानों के जरिए यह साबित होता है कि उन्हें एनडीएफबी संवर्ग के सदस्यों के रूप में भर्ती किया गया था। उन्होंने यह बताया कि उनके जिले में एनडीएफबी संवर्ग के अपराधी कार्यकर्ताओं को मुख्यतः गैर-बोडो नागरिकों के विरुद्ध निर्देशित किया गया था।

पीडब्ल्यू-10, श्री पंकज शर्मा, पुलिस अधीक्षक, उदलगुडी जिला, असम ने यह बयान दिया कि 8-2-2007 का शपथ-पत्र उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने दस्तावेज ई एक्स. पी डब्ल्यू-10/1, ई एक्स. पी डब्ल्यू-10/1(1), ई एक्स. पी डब्ल्यू-10/2, ई एक्स. पी डब्ल्यू-10/3, ई एक्स. पी डब्ल्यू-10/3(1), ई एक्स. पी डब्ल्यू-10/4, ई एक्स. पी डब्ल्यू-10/4(1), ई एक्स. पी डब्ल्यू-10/5(1) से ई एक्स. पी डब्ल्यू-10/5(7) और ई एक्स. पी डब्ल्यू-10/6(1), ई एक्स. पी डब्ल्यू-10/6(3) को साबित किया। मूल दस्तावेज देखे गए और लौटा दिए गए। दस्तावेजों से एनडीएफबी संवर्ग के सदस्यों से हथियारों और गोलाबारूद की बरामदगी साबित होती है। उनके पास एनडीएफबी काडर के गिरफ्तार किए गए सदस्यों के उनकी संलिप्तता को स्वीकारते हुए अभिकथन हैं। ये दस्तावेज एनडीएफबी काडर सदस्यों द्वारा अपहरण किए गए व्यक्तियों से संबंधित एफआईआर हैं। उसने बताया कि उनके जिले में जबरन धन-वसूली, अपहरण, हत्या और विस्फोट की घटनाओं का ब्यौरा ई एक्स. पी डब्ल्यू-1/3 में है जो गैर-बोरो नागरिकों के खिलाफ निर्देशित थी। गवाह ने बताया कि एफआईआर, प्रदर्श-सरकारी गवाह 10/4 के अनुसरण में की गई अगली जांच से यह प्रदर्शित हुआ कि बुबुल कलिता के साथ सशस्त्र सेवा बल के कैप्टन पी रोगी सिंह, कैप्टन एच, लक्षाब सिंह, कैप्टन थिंगाल्का वाईफई, कैप्टन अमोंगवा संगथाम और कैप्टन कुक कृष्ण बहादुर चेन्नी नामक 5 कार्मिकों का अपहरण किया गया था। इनमें से सभी की हत्या कर दी गई थी और इनके शव असम-अरुणाचल सीमा के पास में बेलशिर की पहाड़ियों की तलहटी से बरामद हुए थे। उन्होंने आगे बताया कि वे वाहन भी बरामद हो गए जिनमें अपहृत व्यक्तियों को ले जाया गया था। इसमें भीकराज, हालिया और गाला सभी एनडीएफबी कार्यकर्ता संलिप्त थे।

सरकारी गवाह-11, सत्येन्द्र नारायण सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गुवाहाटी सिटी, असम ने बताया कि उन्होंने 10-2-2007 को हलफनामा पी-11 में साक्ष्य दिया था। उन्होंने प्रदर्श सरकारी गवाह 11/1, ई एक्स. पी डब्ल्यू-11/2, ई एक्स. पी डब्ल्यू-11/3(1) और ई

देखकर वापस कर दिया गया। दर्ज किए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उन्होंने एनडीएफबी काडर सदस्य से जब्त की गई एक डायरी भी प्रस्तुत की जिसमें जबर्न धन वसूली करने वाले 18 काडर सदस्यों के नामों की सूची थी। उसमें जबर्न धन वसूली करने के लिए विभिन्न स्थानों को 11-7-2004 से 23-9-2004 तक भेजे गए एनडीएफबी काडर सदस्यों पर हुए व्यय को रिकार्ड किया गया था। गवाह द्वारा साबित किए गए दस्तावेजों में एनडीएफबी सदस्यों द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को लिखे गए जबर्न धन वसूली पत्र थे।

ई एक्स. पी डब्ल्यू-11/4 राज्य आसूचना द्वारा बरामद एक पत्र था। यह कमाण्ड-एनडीएफबी के रूप में बी.सूडेम और बी. जैकलांग द्वारा संबोधित किया गया है। यह भूटान में डी.सी दासु को सम्बोधित है। इस पत्र में बताया गया है कि बोरो जाति भूटानी मंगोलिआई मूल की है। इस पत्र में भूटानी लोगों से सहयोग की मांग की गई है।

सरकारी गवाह-12, श्री एम.पी. गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जिला-सोनितपुर, असम ने बताया कि उसने साक्ष्य के रूप में हलफनामा पी-12 दिनांक 7-2-2007 दिया है। उन्होंने दस्तावेज संख्या ई एक्स. पी डब्ल्यू-12/1, ईएक्स. पीडब्ल्यू-12/2(1), ईएक्स. पीडब्ल्यू-12/2(2), ईएक्स. पीडब्ल्यू-12/2(3), ईएक्स. पीडब्ल्यू-12/2(4), ईएक्स. पीडब्ल्यू-12/3, ईएक्स. पीडब्ल्यू-12/4(1), ईएक्स. पीडब्ल्यू-12/4(2), ईएक्स. पीडब्ल्यू-12/4(3), को सिद्ध किया है। मूल दस्तावेज देखकर वापिस कर दिए गए थे। गवाह द्वारा साबित किए गए दस्तावेजों में शस्त्र एवं गोला बारूद, मोबाइल टेलीफोन, नकदी तथा अन्य अभिशंसात्मक दस्तावेजों की जब्ती को सिद्ध किया गया है। इन दस्तावेजों में गिरफ्तार एनडीएफबी उग्रवादियों द्वारा उनकी संलिप्तता स्वीकार करते हुए अभिकथन और शस्त्रों की बरामदगी है। ये दस्तावेज जबर्न धन संग्रहण के साक्ष्य के रूप में धन की रसीदें हैं।

पीडब्ल्यू-13 आर. आर. झा, निदेशक, भारत सरकार, गृह मंत्रालय ने बताया कि उन्होंने प्राप्त सूचना राज्य सरकार और विभिन्न एजेंसियों द्वारा उन्हें भेजी गई सूचना के अनुसार हलफनामा पी-13 साक्ष्य के रूप में दिया था। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट के अनुलग्नक-1 में दर्शाए गए एनडीएफबी के पदधारियों के नाम प्राप्त आसूचना रिपोर्टों के अनुरूप थे। इसी तरह उक्त अनुलग्नक में एनडीएफबी के उत्तर-पूर्व में सक्रिय अन्य अलगाववादी संगठनों के साथ संबंध तथा अन्य विदेशी संबंधों का उल्लेख आसूचना रिपोर्टों के अनुरूप था। यह पूछे जाने पर कि क्या गवाह कुछ आसूचना रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है, गवाह ने सकारात्मक उत्तर दिया और उन्होंने गृह मंत्रालय को आसूचना ब्यूरो, महानिदेशक, सीआरपीएफ (प्रचालन शाखा) अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक तथा असम सरकार से प्राप्त कुछ रिपोर्टें प्रस्तुत कीं। हलफनामा के अनुलग्नक-2 में उल्लिखित एनडीएफबी सदस्यों द्वारा की गई हिंसा की प्रमुख घटनाएं आसूचना ब्यूरो द्वारा 24-7-2006 को प्रस्तुत रिपोर्ट पर आधारित थी। रिपोर्ट की फोटोकापी लगाई गई थी। (इनका गहन अध्ययन किया गया और सीलबंद लिफाफे में रख ली गई)। उन्होंने बताया कि एनडीएफबी काडर सरकारी कर्मचारियों को भी निशाना बना रहे हैं और बोडो नागरिकों जो एनडीएफबी की विचारधारा का विरोध करते हैं, को भी तंग किया जा रहा है।

रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्यों से सिद्ध होता है कि सशस्त्र संघर्ष के जरिए भारत की अखण्डता एवं संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने के लिए एनडीएफबी के संविधान के अनुसार उसकी विचारधारा और बोडोलैंड की स्थापना का अभी भी हिंसा के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है। एनडीएफबी की अपनी गतिविधियां स्थगित रखने के लिए बाध्य करने वाले समझौते के बावजूद आपराधिक गतिविधियां जारी हैं। साक्ष्यों से 76 ऐसी घटनाएं पुष्टि होती हैं जिनमें हिंसा का सहारा लिया गया था। जबर्न धन-वसूली और उसके प्रयासों से वास्तव में जो धन एकत्रित किया जाता है उसे हिंसक गतिविधियों के लिए दिया जाता है। ई एक्स. पी डब्ल्यू-11/4 सीमा पार से बाहरी प्राधिकरणों से संरक्षण प्राप्त करने का प्रयोजन प्रदर्शित करता है। रिकार्ड किए गए साक्ष्यों से यह सिद्ध होता है कि असम राज्य में 13 जिले प्रभावित हैं।

एनडीएफबी को 23-11-1992 को विधिविरुद्ध संगठन घोषित किया गया था और इसे विधिविरुद्ध संगठन घोषित करना जारी रखने की उत्तरवर्ती अधिसूचनाओं के बावजूद आपराधिक गतिविधियां जारी हैं।

उल्लिखित साक्ष्यों के मूल्यांकन से दो बातें ध्यान में रखनी होंगी। अधिकरण द्वारा न्याय निर्णय करने के प्रयोजनों के लिए क्या इसके द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत रिकार्ड किए गए बयान पर विचार किया जा सकता है अथवा नहीं।

भारत संघ बनाम स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया एंड अदर्स 99 (2002) डीएलटी 147 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की :-

“सरकार ने जिन इकबालिया बयानों का हवाला दिया है तथा भरोसा किया है, उन्हें उन आपराधिक मामलों की जांच-पड़ताल के दौरान रिकार्ड किया गया था जिनके तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया था। साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 में यह व्यवस्था की गई है कि किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई कोई भी स्वीकारोक्ति किसी अपराध के अभियुक्त के खिलाफ साबित नहीं की जाएगी।

‘किसी अपराध का अभियुक्त’ अभिव्यक्ति उस व्यक्ति की ओर संकेत करती है जिसके खिलाफ किसी आपराधिक मामले में साक्ष्य साबित किया जाना है। अतः, विशेषण खंड 1 ‘किसी अपराध का अभियुक्त’ उस व्यक्ति की ओर संकेत करता है जिसके खिलाफ कोई स्वीकारोक्ति साबित की जानी है। इकबालिया बयानों को दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सिविल कार्यवाहियों तथा अन्य पाश्वक कार्यवाहियों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस अधिकरण को स्पष्ट रूप से उन अभियुक्तों के खिलाफ विचारण की जांच नहीं करनी है जिन्होंने इकबालिया बयान दिए हैं। अतः, मेरी राय में विभिन्न मामलों की जांच-पड़ताल के दौरान अभियुक्तों द्वारा पुलिस अथवा न्यायालय के समक्ष दिए गए इकबालिया बयानों पर साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 लागू नहीं होगी और ये बयान साक्ष्य में यह दर्शाने के लिए अनुपयोगी होंगे कि क्या अभियुक्त संघ के सदस्य थे अथवा हैं और यह भी दर्शाने के लिए कि क्या संघ के क्रियाकलाप विधिविरुद्ध है अथवा नहीं।”

सुमन एवं अन्य आदि बनाम तमिलनाडु राज्य एआईआर 1986 (मद्रास) 318 में यह फैसला दिया गया :

“यह याद रखा जाना चाहिए कि जब धारा 25 किसी ऐसी स्वीकारोक्ति का हवाला देती है जिसे किसी अपराध के अभियुक्त के खिलाफ साबित करने की अनुमति नहीं होती तो यह अभियुक्त द्वारा की गई ऐसी स्वीकारोक्ति का हवाला देती है जिसे किसी अपराध को सिद्ध करने के लिए उसके खिलाफ साबित किए जाने का प्रस्ताव किया गया हो। अतः धारा 25 का दायरा किसी ऐसे व्यक्ति, जो अभियुक्त हो, द्वारा की गई स्वीकारोक्ति तक ही सीमित है जिसे उसके खिलाफ कोई अपराध सिद्ध करने के लिए की जा रही कार्यवाही में प्रयोग किया जा रहा है।”

जहां तक इस बात का संबंध है कि सामग्री क्या है और उस पर अधिकरण द्वारा किस प्रकार विचार किया जाना चाहिए, यह उच्चतम न्यायालय द्वारा जमात-ए-इस्लामी हिंद बनाम भारत संघ, जे टी 1995(1) एस.सी. 31 में उल्लेख किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित फैसला दिया :

“धारा 4 का संबंध अधिकरण से है। उप-धारा (1) में यह अपेक्षित है कि केन्द्र सरकार को ‘यह न्यायनिर्णय लेने के प्रयोजन से कि क्या संगम को विधिविरुद्ध घोषित करने के पर्याप्त कारण विद्यमान हैं या नहीं’, अधिकरण की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना का हवाला देना है। अधिकरण का हवाला देने का प्रयोजन है अधिकरण द्वारा घोषणा करने के लिए पर्याप्त कारण मौजूद होने का न्यायनिर्णय करना। इस संदर्भ में ‘न्यायनिर्णय’ तथा ‘पर्याप्त कारण’ शब्द महत्वपूर्ण हैं। उप-धारा (2) में अपेक्षित है कि अधिकरण हवाला प्राप्त होने पर, प्रभावित संघ को ‘लिखित में कारण बताओ नोटिस देकर’ यह पूछे के इस संघ को विधि-विरुद्ध क्यों न घोषित किया जाए। यह अपेक्षा तब तक निरर्थक होगी जब तक कि उस आधार का प्रभावी नोटिस न हो जिस आधार पर घोषणा की गई है और उसके खिलाफ कारण बताने का युक्तिसंगत अवसर न हो। उप-धारा (3) में उक्त नोटिस के उत्तर में कारण बताए गए, कारण पर विचार करने के बाद विनिर्दिष्ट तरीके से अधिकरण द्वारा जांच करना विहित है। अधिकरण यह निर्णय लेने के लिए कि उक्त संगम को विधिविरुद्ध घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण विद्यमान हैं या नहीं, केन्द्र सरकार से यथावश्यक सूचना भी मांग सकता है। अधिकरण को एक आदेश देना होगा, जो यह उचित समझे, जिसके तहत ‘अधिसूचना में दी गई घोषणा की पुष्टि की गई हो अथवा उसे रद्द किया गया हो।’ अधिकरण द्वारा की जाने वाली जांच के स्वरूप में यह अपेक्षित है कि यह उस सामग्री पर मनन करे जिसके आधार पर धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई है, उक्त संगम को जारी किए गए नोटिस के उत्तर में इसके द्वारा बताए गए कारण पर मनन करे और ऐसी अतिरिक्त सूचना पर विचार करे जो इसमें

मांगी हो ताकि उक्त संगम को विधिविरुद्ध घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण की मौजूदगी के बारे में निर्णय लिया जा सके। पूरी प्रक्रिया में दोनों पक्षों द्वारा अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत सामग्री पर आधारित उद्देश्य निर्धारण पर विचार किया गया हो तथा जांच दोनों पक्षों के मध्य एक सूची के न्याय निर्णयन से संबंधित है जिसका परिणाम उनके द्वारा प्रस्तुत सामग्री के तैयार करने वाले पर निर्भर करता है। साधारणतया सामग्री इतनी विश्वसनीय होनी चाहिए कि उससे उद्देश्यपरक मूल्यांकन करना संभव हो सके। अधिकरण को यह निर्णय करना है कि क्या उक्त संगम को विधिविरुद्ध घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण विद्यमान हैं या नहीं। ऐसे निश्चय के लिए अधिकरण को यह निष्कर्ष निकालना आवश्यक है कि घोषणा के समर्थन में प्रस्तुत सामग्री घोषणा के विरोध में प्रस्तुत सामग्री से अधिक पुख्ता है तथा घोषणा के समर्थन में दिया गया अतिरिक्त महत्व इसे बरकरार रखने के लिए काफी है। अधिक संभाव्यता का परीक्षण इस संदर्भ में लागू होने वाला व्यावहारिक परीक्षण प्रतीत होता है।”

उच्चतम न्यायालय ने पैरा 14 में आगे यह निर्णय दिया है :-

“धारा 4 में ‘न्यायनिर्णयन’ तथा ‘निर्णय’ शब्दों का उच्च न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश द्वारा गठित अधिकरण द्वारा की जा रही जांच के संदर्भ में वैधानिक अर्थ है। अधिकरण द्वारा ‘कारण बताओ नोटिस’ के पश्चात् विवादित मुद्दों के संबंध में ‘न्यायनिर्णयन’ की प्रक्रिया द्वारा ‘निर्णय’ लिया जाना अपेक्षित है। ये किसी भी न्यायिक निर्णय के आवश्यक गुण हैं।”

(जोर दिया गया)

“भारत संघ बनाम तुलसीराम पटेल ए.आई.आर. 1985 एचसी 1416 मामले में न्यायालय की संवैधानिक पीठ को विभिन्न अधिनियमों में प्रयोग होने वाली अभिव्यक्तियों जैसे कि ‘कानून एवं व्यवस्था’ ‘लोक व्यवस्था’ ‘राज्य की सुरक्षा’ पर विचार करने का अवसर प्राप्त हुआ। निर्णय के पैरा 140 में माननीय न्यायाधीशों ने निम्नानुसार टिप्पणी की :

“कानून एवं व्यवस्था”, “लोक व्यवस्था” तथा “राज्य की सुरक्षा” जैसी अभिव्यक्तियों का विभिन्न अधिनियमों में प्रयोग किया गया है। “लोक व्यवस्था” को प्रभावित करने वाली परिस्थितियां “कानून एवं व्यवस्था” को प्रभावित करने वाली परिस्थिति से अधिक गम्भीर होती हैं तथा “राज्य की सुरक्षा” को प्रभावित करने वाली स्थितियां उन स्थितियों से गंभीर होती हैं जो “लोक व्यवस्था” को प्रभावित करती हैं। अतः ऐसी स्थिति में सबसे अधिक गंभीर स्थितियां वह होती हैं जो “राज्य की सुरक्षा” की सुरक्षा को प्रभावित करती हैं। राज्य की सुरक्षा को खतरा राज्य के भीतर से या कहीं बाहर से हो सकता है। “राज्य की सुरक्षा” शब्द से अभिप्राय सम्पूर्ण देश अथवा पूरी राज्य की सुरक्षा से नहीं है। इसमें राज्य के किसी एक हिस्से की सुरक्षा शामिल है। इसे किसी

सशस्त्र विद्रोह अथवा बगावत तक सीमित नहीं किया जा सकता। ऐसे बहुत से माध्यम हैं जिनके द्वारा राज्य की सुरक्षा को प्रभावित किया जा सकता है। इसे राज्य के गुप्त भेदों अथवा रक्षा उत्पाद संबंधी सूचनाओं अथवा इसी तरह की सामग्री को हमारे देश के मित्र अथवा शत्रु राष्ट्र को हस्तांतरण करके अथवा आतंकवादियों के साथ गुप्त संबंधों द्वारा प्रभावित किया जा सकता है। राज्य की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले विभिन्न तरीकों को गिनाना कठिन है। राज्य की सुरक्षा को प्रभावित करने का तरीका या तो स्पष्ट अथवा प्रच्छन्न हो सकता है।”

उक्त परीक्षण को लागू करते हुए तथा रिकार्ड के लिए प्रस्तुत सामग्री पर विचार करते हुए मेरा यह सुविचारित मत है कि अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत सामग्री विश्वसनीय थी तथा इसका खण्डन न किए जाने के कारण इसे स्वीकार करना ही होगा। उस साक्ष्य के अलावा, जिसके बारे में मैंने ऊपर चर्चा की है, राज्य के पास सूचनाएँ देने हेतु आसूचना ब्यूरो तथा अन्य गुप्त अधिकरण भी है। अधिकरण को सामग्री दिखाई गई थी। गुप्त सूचना जिसका अवलोकन अधिकरण द्वारा किया गया है, में कहा गया है कि बोडो लोगों के पाकिस्तानी आईएसआई सहित अन्य आतंकवादी संगठनों के साथ संबंध हैं। रिपोर्ट में निम्नानुसार कहा गया है। अतः, अधिकरण को इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि एनडीएफबी, इसके सदस्यों, अनुयायियों, इसके साथ सहानुभूति रखने वाले लोगों की गतिविधियाँ विध्वंसक हैं। उनकी गतिविधियाँ विघटनकारी हैं तथा भारत की भूभागीय अखंडता और संप्रभुता के विरुद्ध हैं। अतः, दिनांक 23-11-2006 की अधिसूचना के अनुसरण में एनडीएफबी को “विधिविरुद्ध संगम” घोषित किए जाने के पर्याप्त कारण विद्यमान हैं और उक्त अधिसूचना की संपुष्टि की जाती है।

उपर्युक्त के अनुसार पत्र का उत्तर दे दिया गया है।

14 मई, 2007

ह./-

(प्रदीप नन्द्राजोग)

विधि-विरुद्ध कार्यकलाप (निवारण) अधिकरण

[सं. 11011/48/2006-एन.ई.3 III]

नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd May, 2007

S.O. 801(E).— In terms of Section 4 (4) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the order of the Tribunal presided over by Hon'ble Justice Shri Pradeep Nandrajog, Judge, Delhi High Court, to whom a reference was made under Section 4(1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the associations, namely the National Democratic Front of Boroland (NDFB) Organisation of Assam as unlawful is published for general information :

REPORT OF THE UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) TRIBUNAL CONSISTING OF HON'BLE MR. JUSTICE PRADEEP NANDRAJOG, JUDGE, DELHI HIGH COURT.

In exercise of powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (Act No. 37 of 1967) (hereinafter referred to as the 'Act'), vide notification No. 2008(E) dated 23-11-2006 the Government of India has declared National Democratic Front of Boroland (hereinafter referred to as the 'NDFB') as 'Unlawful Association'.

The Government of India came to the conclusion that NDFB was Unlawful Association on the grounds that notwithstanding having agreed to abjure violence, NDFB has continued to :—

- (i) indulge in various illegal and violent activities intended to disrupt or which disrupt the sovereignty and territorial integrity of India in furtherance of its objective of achieving a separate Bodoland;
- (ii) align itself with other unlawful associations like the United Liberation Front of Asom and outfits like the National Socialist Council of Nagaland (Isac-Muviah) to create a separate Bodoland;
- (iii) in pursuance of its aims and objectives, engaged in several unlawful and violent activities thereby undermining the authority of the Government and spreading terror and panic among the people;
- (iv) indulge in extortions of money from businessmen, Government officials and other civilians in addition to acts of kidnapping for ransom with a view to finance and execute plans for creation of a separate Bodoland;
- (v) embark on a systematic drive for recruitment of fresh cadres with a view to continuing its terrorist and insurgency activities;
- (vi) create carnage and ethnic violence resulting in killings, destruction of property and exodus of thousands of non-Bodos inhabiting in Bodo dominated areas in Assam with a view to spread panic and insecurity among non-Bodos and forcing them to migrate from Bodo areas;
- (vii) establish camps and hideouts across the Country's border to carry out its secessionist activities;
- (viii) obtain assistance from, anti-India forces in other countries to procure arms and other assistance in their struggle for creation of a separate Bodoland.

2552 GI/07-3

The Union of India has noted that the violent activities of NDFB include :—

- (i) 58 violent incidents in 2004, killing 60 persons including one personnel of security forces;
- (ii) 21 violent incidents in 2005, killing 4 persons;
- (iii) 15 violent incidents in 2006 (up to 31st August, 2006) killing 9 persons including 5 personnel of security forces.

On the afore-noted grounds and afore-noted violent activities, the Government of India formed an opinion that activities of NDFB are detrimental to the sovereignty and integrity of India and that unless the unlawful activities of NDFB are kept under control, NDFB may re-group and re-arm itself, make fresh recruitments, indulge in violence, terrorist and secessionist activities, collect funds and endanger the lives of innocent citizens and security personnel; and therefore, circumstances do exist which render it necessary to declare NDFB as unlawful Association with immediate effect.

Exercising powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the Act, Ministry of Home Affairs, Government of India, vide notification No. S. O. 2120(E) dated 19-12-2006, constituted this Tribunal for the purpose of adjudicating whether or not there were sufficient grounds for declaring NDFB as Unlawful Association and made reference to this Tribunal under the provisions of Section 4 of the Act.

The reference was received by this Tribunal on 22-12-2006.

Having received the reference, *vide* order dated 22-12-2006, this Tribunal listed the reference for preliminary hearing on 4-1-2007.

After perusing the reference, in pursuance of the provisions of Sub-section (2) of Section 4 of the Act, *vide* order dated 4-1-2007 this Tribunal issued notice to NDFB to show-cause, in writing, within 30 days from the date of service of the notice as to why NDFB should not be declared Unlawful Association. *Vide* said order, the Tribunal directed that the notice shall be served on NDFB by publication in 2 daily national and 2 local newspapers circulated and published in the locality where NDFB has its establishments or presence is known in the State of Assam and outside, as well as by broadcasting on radio, television and by proclamation, by beat of drums or by means of loudspeakers in the areas in which activities of NDFB are ordinarily carried out.

It was additionally directed that the notice should also be served by pasting on the notice board of the office of each District Magistrate/Tehsildar at the Headquarters of the District or Tehsil, as feasible.

Service of the notice upon NDFB was directed to be effected within 2 weeks. The service report, duly supported by the affidavits of the concerned officers/officials, who

effected the service was directed to be filed within 2 weeks thereafter alongwith supporting documents.

It was further directed that sitting of the Tribunal would ordinarily be at New Delhi, but as and when required, Tribunal would hold sittings in the State of Assam or any other place.

Affidavit of service was filed by Mr. A. K. Goyal, Director, Government of India, Ministry of Home Affairs, New Delhi, stating therein that pursuant to the order dated 04-01-2007 passed by this Tribunal, a notice dated 6-1-2007, 4-1-2007 passed by the Government of India to the Chief Secretary, Government of Assam for taking necessary action to serve the notice. It was stated in the affidavit that the Government of Assam took the following steps for effecting service of the notice :

- (i) The Notice was published in four local newspapers, namely 'The Amar Asom' dated 19-01-2007, 'The Assam Tribune' dated 19-01-2007, 'Dainik Jagran' dated 21-01-07 and 'Indian Express' dated 22-01-2007 as per Annexure I to IV.
- (ii) According to the Government of Assam the Notice was telecasted and broadcasted from Doordarshan Kendra, Guwahati as per Annexure-V.
- (iii) According to the Government of Assam the Notice as broadcasted in Regional News Bulletin through the Guwahati Station of the All India Radio on 01-02-2007 as per Annexure-VI.
- (iv) According to the Government of Assam the news of banning of NDFB was telecasted in evening Assamese Bulletin at 7.00 P.M. on 23-01-2007 through Doordarshan Kendra, Guwahati as per Annexure VII.
- (v) The notice was also affixed/served at conspicuous places publicly and prominently in thirteen districts of the State of Assam as per Annexure VIII.

Affidavit of service was also filed by Mr. S. K. Roy, Joint Secretary to the Government of Assam, Political (A) Department, Assam Secretariat, Dispur, Guwahati in which it was stated that the notice was published in the national English Newspaper "Indian Express" on 22-1-2007, the national Hindi Newspaper "Dainik Jagran" on 22-01-2007, the vernacular Assamese newspaper "Amar Asom" on 19-01-2007 and the local English Newspaper "Assam Tribune" on 19-01-2007. The contents of the notice were covered in the Regional New Bulletin at 9.25 P.M. of the All India Radio, Guwahati on 01-02-2007. Doordarshan Kendra, Guwahati telecasted the contents of the notice in the evening regional Assamese News Bulletin at 7.00 P.M. on January 23-01-2007. That the notice was also served by way of beating of drum/announcement through

loudspeakers in conspicuous places/hats/bazars, pasting of notice at the office of District Magistrate/Tehsildar and the Police Station and by serving the notice on family members of known NDFB activities in presence of independent witnesses and such exercise has been carried out in various Districts of Assam where the unlawful organization (NDFB) has been carrying out its activities.

At the hearing held by the Tribunal on 28-2-2007, on perusing the affidavits filed, satisfaction was recorded by the Tribunal that order dated 4-1-2007 had been complied held within the time granted for effecting service. NDFB was duly served. It was noted that objections/replies/written statements have not been filed by or on behalf of NDFB within the time granted i.e. 30 days from the date of service of notice. It was also noted that none appeared on behalf of NDFB either in person or through counsel. Thus, the Tribunal directed that further inquiry would be conducted ex-parte.

Thus, NDFB was duly served with the notice as per directions of the Tribunal prescribed under Rule 6 of the Unlawful Activities (Prevention) Rules, 1968 and chose not to participate in the proceedings conducted by the Tribunal.

The Government of Assam led evidence by way of affidavits supported with documents of the following officers:—

- (1) Shri S.K. Roy son of Shri late S.S.Roy, Joint Secretary to the Government of Assam, Home and Political Department, Assam Sachivalaya; Dispur, Guwahati.
- (2) Shri Arabinda Kalita son of Shri Matiram Kalita R/o Dispur, Guwahati, Superintendent of Police, Special Operation Unit, Special Branch, Assam, Kahilipara, Guwahati.
- (3) Shri Debraj Upadhyaya, APS, Superintendent of Police, Barpeta District.
- (4) Shri Abhijit Bora, APS, Superintendent of Police, Goalpara District.
- (5) Shri K.J. Saikia, APS, serving as superintendent of Police, Baksa District.
- (6) Shri Pradip Pujari, APS, serving as Superintendent of Police, Chirang District.
- (7) Shri Anurang Tankha, IPS, serving as Superintendent of Police, Karbi Anglong District, Diphu.
- (8) Shri Hiren Chandra Nath, IPS, serving as Superintendent of Police, Kokrajhar District.
- (9) Shri Parth Sarathi Mahanta, APS, Superintendent of Police, Dhubri District.
- (10) Shri Pankaj Sharma, APS, serving as Superintendent of Police, District Udalguri.

- (11) Shri Satyendra Narayan Singh, IPS, serving as Senior Superintendent of Police, City Guwahati.
- (12) Shri M.P. Gupta, IPS, Superintendent of Police, Sonitpur District, Assam.

Government of India sought 2 weeks further time to lead evidence. Time was granted.

Hearing was held by the Tribunal at Shillong, Hotel Pinewood on 4-4-2007. Mr. S.K.Roy, Joint Secretary, Government of Assam, Home and Political Department, Dispur, Guwahati, placed on record the extracts of the daily newspapers viz. 'The Indian Express' dated 2-4-2007, 'The Assam Tribune, Guwahati' dated 1-4-2007, 'Dainik Jagran' dated 1-4-2007, 'Bodosa' (Daily in Bodo Language) dated 2-4-2007, 'Sanseyari Bodoland Engkhong: Bijni' dated 2-4-2007, 'Asomiya Khobar' dated 2-4-2007 and 'Aazi' dated 2-4-2007 evidencing public notice that the Tribunal would be holding sittings at Shillong on 4th, 5th and 7th April, 2007 at 10-30 P.M.

Nobody represented NDFB during course of sittings at Shillong on 4th, 5th and 7th April, 2007. No public citizen participated in the inquiry on said dates.

Government of India filed an affidavit by way of evidence of Shri R.R.Jha, Director to Government of India, Ministry of Home Affairs. The affidavit was supported with documents.

As per affidavit P-1 filed by PW-1, Shri S.K. Roy, Joint Secretary, Government of Assam, Home and Political Department (Dispur), Guwahati, statement of incidents attributable to NDFB from 22-11-2004 to 22-11-2006 were listed in a chart Ex. PW-1/3. The data compiled in said exhibit was as per information received from 13 administrative districts in the State of Assam. The witness proved that a suspension of activities agreement was signed on 24-5-2005 between NDFB, Government of Assam and Government of India. He proved the said agreement being Ex.PW-1/2(1). On behalf of NDFB, agreement was signed by B.Swmkhwr @ Gobind Basumatary. He proved Ex.PW-1/2(2) being agreement dated 27-5-2006 extending the previous agreement, Ex. PW-1/2(1), for a further period of 6 months. He further proved agreement dated 28-11-2006, Ex. PW-1/2(3), extending the initial agreement of suspension of operation by further 6 months beyond 1-12-2006.

Witness stated that the peace process and the political dialogue with NDFB was not making any meaningful progress because NDFB has not furnished a charter of demands for consideration by the Government envisaged by Ex. PW-1/2(1). Witness stated that intelligence reports revealed that hard-core members of NDFB were in active liaison with other banned organizations as also with ISI and other extremist organizations based in foreign territories. He also proved Ex. PW-1/4(1), Ex.PW-1/4(2), Ex.PW-1/5(1), Ex.PW-1/5(2) and Ex. PW-1/6(2) where from it could be gathered that

cadre of NDFB was interacting with other banned organizations, ISI and extremist organizations based in foreign territories. He stated that the incidents of extortion, kidnapping and murder detailed in Ex. PW-1/3 are mainly directed against non-Boro citizens in the State of Assam.

PW-2, Shri Arabinda Kalita, Superintendent of Police (SOU), Special Branch, Assam Kahilipara, Guwahati deposed that affidavit dated 9-2-2007, P-2 was deposed to by him. He stated that Ex. PW-1/4(1), Ex. PW-1/4(2), Ex. PW-1/4(3), Ex. PW-1/5(1), Ex. PW-1/5(2), Ex. PW-1/5(3), Ex. PW-1/6(1), and Ex. PW-1/6(2), were the extracts of debriefing statements of Benu Boro Sohilton Narzary and Gobinda Basumatary, office bearers of NDFB. He stated that he provided the said extracts to the Government of Assam, Home and Political Department and were filed along with the affidavit of PW-1. He further stated that Ex. PW-1/8(1), Ex. PW-1/8(2), Ex. PW-1/8(3), Ex. PW-1/8(4), Ex. PW-1/8(5) and Ex. PW-1/8(6) were made available to him by the concerned police officers of the respective police stations to him and that he forwarded the same to the Government of Assam, Home and Political Department. He further stated that Ex. PW-1/9(1), Ex. PW-1/9(2) and Ex. PW-1/9(3) were made available by his office to PW-1.

The witness produced originals of all aforementioned documents.

He further stated that as per intelligence reports, a gentlemen called Ranjan Daimary is currently holding himself out to be the Chairman/President of NDFB and was in Bangladesh. He stated that intelligence reports informed that NDFB was having camps at 3 sites in Chittagong Hills in Bangladesh at Rangamati, Balsori and Monikura. He further stated that intelligence reports indicated that NDFB cadre was in touch with other secessionist/terrorist organizations such as NSCN(IM), NIFT, PLA (Manipur), ULFA, ANBC, HNLC as also ISI and DGFI. He further stated that intelligence reports indicated that NDFB was in touch with underground movements headed by Arakan Myanmar and Khymer Rouge. The witness corroborated PW-1 that incidents of kidnapping, extortion and murder detailed in Ex. PW-1/3 were mainly directed against non-Boro citizens in the State of Assam.

PW-3, Shri Debaraj Upadhaya, Superintendent of Police, Barpeta District, Assam stated that the affidavit P-3 dated 8-2-2007 was deposed to by him. He proved documents Ex. PW-3/1, Ex. PW-3/2(1) to Ex. PW-3/2(4), Ex. PW-3/3(1) to Ex. PW-3/3(3), Ex. PW-3/4(1), Ex. PW-3/5, Ex. PW-3/6(1) to Ex. PW-3/6(3), Ex. PW-3/7, Ex. PW-3/8, Ex. PW-3/9(1) to Ex. PW-3/9(3) and Ex. PW-3/10. Original documents were produced. The said documents establish that on 5-4-2005 information was received at PS Sorbhogh that NDFB cadre was indulging in an extortion drive. A police team accompanied by the 93 battalion of CRPF went to areas of Helosiguri, Odalguri, Mainamata, Labdanguri and Samthaibari. Local investigation revealed that accused persons had extorted money from citizens of Assam in said areas.

Ex. PW-3/1 to Ex. PW-3/10 were copies of GD entries, extortion notices handed over by people in the affected areas, seizure memos, statements of persons recorded under Sections 161 Cr. P.C. that NDFB cadre was threatening them and other persons to part with money under threat of physical harm.

PW-4, Shri Abhijit Bora, Superintendent of Police, Golpara District, Assam stated that affidavit P-4 dated 6-2-2007 was deposed to by him. He proved Ex. PW-4/1, Ex. PW-4/2, Ex. PW-4/3(1), Ex. PW-4/3(2) and Ex. PW-4/4. Original documents were produced by him. The documents, Ex. PW-4/1 to Ex. PW-4/4 evidence extortion by NDFB cadre in the State of Assam. Seizure memos revealed extortion letters issued by NDFB cadre to the citizens in the area. Ex. PW-4/4 is a statement of Captain V.K. Sharma to the effect that he apprehended one Lakhman Singh Brahma who had with him extortion letters on letterheads of NDFB. Ex. PW-4/4(1), Ex. PW-4/4(2), Ex. PW-4/4(3), Ex. PW-4/4(4), Ex. PW-4/4(5), Ex. PW-4/4(6), Ex. PW-4/4(7), Ex. PW-4/4(8), Ex. PW-4/4(9), Ex. PW-4/4(10), Ex. PW-4/4(11) and Ex. PW-4/4(12) are statements of various persons who were issued extortion letters and who had witnessed arrest of Boro youths extracting money from shopkeepers in the area.

PW-5, Shri Kangkan Jyoti Saikia, Superintendent of Police, Baksa District, Assam stated that affidavit P-5 dated 7-2-2007 was deposed to by him. He proved Ex. PW-5/1, Ex. PW-5/2(1), Ex. PW-5/3(1) to Ex. PW-5/3(5), Ex. PW-5/4, Ex. PW-5/5, Ex. PW-5/6(1) to Ex. PW-5/6(3), Ex. PW-5/7, Ex. PW-5/8, Ex. PW-5/9, Ex. PW-5/10, Ex. PW-5/11(1) and Ex. PW-5/11(2). Original documents were produced. The said documents consist of DD Entry, FIRs and statements of witnesses and pertain to extortion threat by NDFB cadre. Ex. PW-5/9 is the statement of Captain Ashis Pandey, 16, Garhwal Rifles to the effect that he apprehended one Ranjit Guyan and Bedamgtha Basumatary from Darranga Mela Bazar when they were collecting money from shopkeepers under threat of physical harm. Ex. PW-5/9 is the recovery memo showing recovery of Indian currency and Bhutanese currency from the said 2 persons. The witness further stated that in his district 35 NDFB cadre members were arrested in the last 2 years. He stated that incidents of extortions in his district were directed mainly against non-Borao citizens in the State of Assam.

PW-6, Shri Pradip Pujari, Superintendent of Police, Chirang District, Assam stated that affidavit P-6 dated 6-2-2007 was deposed to by him. He proved Ex. PW-6/1, Ex. PW-6/2, Ex. PW-6/3(1), Ex. PW-6/3(2), Ex. PW-6/4(1), Ex. PW-6/4(2), Ex. PW-6/5, Ex. PW-6/6, Ex. PW-6/7(1), Ex. PW-6/8(1) to Ex. PW-6/8(5), Ex. PW-6/9, Ex. PW-6/10, Ex. PW-6/11(1), Ex. PW-6/11(2), Ex. PW-6/12, Ex. PW-6/13(1) to Ex. PW-6/13(5), Ex. PW-6/14(1), Ex. PW-6/14(2), Ex. PW-6/15, Ex. PW-6/16(1) to Ex. PW-6/16(3), Ex. PW-6/17(1), Ex. PW-6/17(2), Ex. PW-6/18(1) to Ex. PW-6/18(3), Ex. PW-6/19(1) to Ex. PW-6/19(4), Ex. PW-6/20(1) to Ex. PW-6/20(2), Ex. PW-6/21(1) to Ex. PW-6/21(3), and Ex. PW-6/22. Original documents were produced. The said documents are

recovery memos, seizure lists and statements not only of witnesses but arrested NDFB cadre members, namely, Ranjit Goyari and Annta Raj Chetry. The statements of arrested cadre are to the effect that they were enticed to join NDFB cadre and that after undergoing training in camps in Bhutan and Sengkari they were assigned duty of collecting money to fund the activities of NDFB. The statements reveal that one Rosan Basumatary was nominated as the platoon commander in the area by NDFB. That NDFB cadre was extorting money from truck drivers in the area. The statements give the name of other NDFB members operating in the area. The statement of affected citizens are to the effect that under threat of physical violence they were being compelled to give money NDFB cadre. Recovery memos evidenced extortion letters addressed by NDFB cadre to the citizens in district Chirang.

PW-6 filed an additional affidavit dated 10-4-2007 proving thereunder Ex. PW-6/11(1), Ex. PW-6/11(2), Ex. PW-6/12, Ex. PW-6/13(1), Ex. PW-6/13(2), Ex. PW-6/13(3), Ex. PW-6/13(4), Ex. PW-6/13(5), Ex. PW-6/14(1), Ex. PW-6/14(2), Ex. PW-6/15, Ex. PW-6/16(1), Ex. PW-6/16(2), Ex. PW-6/16(3), Ex. PW-6/17(1), Ex. PW-6/17(2), Ex. PW-6/18(1), Ex. PW-6/18(2), Ex. PW-6/18(3), Ex. PW-6/19(1), Ex. PW-6/19(1-A), Ex. PW-6/19(20), Ex. PW-6/19(2A), Ex. PW-6/19(3), Ex. PW-6/19(3A-1), Ex. PW-6/19(3A-2), Ex. PW-6/19(4), Ex. PW-6/19(4A), Ex. PW-6/20(1), Ex. PW-6/20(2), Ex. PW-6/21(1), Ex. PW-6/21(1A-1), Ex. PW-6/21(1A-2), Ex. PW-6/21(2), Ex. PW-6/21(2A-1), Ex. PW-6/21(2A-2), Ex. PW-6/21(3) and Ex. PW-6/22. The said documents establish an encounter between NDFB militants and the army on 3-2-2005 and recovery effected from a slain militant. The documents also establish another encounter between the army and NDFB militants on 30-11-2004 and recovery of arms and ammunitions including an AK-47 rifle.

PW-7, Shri Anurag Tankha, Superintendent of police, Karbi Anglong stated that affidavit P-7 dated 7-2-2007 was deposed to by him. He proved documents Ex. PW-7/1, Ex. PW-7/2(1), Ex. PW-7/2(2), Ex. PW-7/3, Ex. PW-7/4(1) to Ex. PW-7/4(3), Ex. PW-7/5, Ex. PW-7/6(1), Ex. PW-7/6(2), Ex. PW-7/7, Ex. PW-7/8(1) to Ex. PW-7/8(4), Ex. PW-7/9(1), Ex. PW-7/9(2), Ex. PW-7/10, Ex. PW-7/11(1), Ex. PW-7/11(2), Ex. PW-7/12(1) and Ex. PW-7/12(2). Originals were seen and returned. The said documents are recovery memos, statements of witnesses, confessional statements of Bharat Boro, a NDFB cadre member disclosing names of other cadre members; confessional statement of Shri Sontosh, another NDFB activist. Seizure lists indicated recovery of extortion letters, arms and ammunitions, Ex. PW-7/8(1) evidences recovery of hand grenades, 9 mm empty cases, mobile phones etc.

PW-8, Shri Hiren Chandra Nath, Superintendent of Police, Kokrajhar District, Assam stated that the affidavit P-8 dated 9-2-2007 was deposed to by him. He proved documents Ex. PW-8/1, Ex. PW-8/2, Ex. PW-8/3(1) to Ex. PW-8/3(8), Ex. PW-8/4, Ex. PW-8/5, Ex. PW-8/6(1) to Ex.

PW-8/6(8), Ex. PW-8/7, Ex. PW-8/8, Ex. PW-8/9, Ex. PW-8/10, Ex. PW-8/10(1) to Ex. PW-8/10(8), Ex. PW-8/11, Ex. PW-8/12, Ex. PW-8/13 and Ex. PW-8/13(1) to Ex. PW-8/13(13). He stated that the incidents of extortion kidnapping and murder in his district were mainly directed against non-Boro citizens in the State of Assam. The documents proved by the witnesses were FIRs, seizure memos, statements of complainants, identification of dead bodies of persons killed by NDFB members, statements of relatives that NDFB members were demanding protection money from the deceased, recovery memos pertaining to arms and ammunitions, diary recording purported details of extortion money received by NDFB cadre members, voluntary disclosure statements of apprehended NDFB cadre members. Ex. PW-8/7 reveals an incident of ambush on the officers of the 11th J & K Light Infantry on 28-1-2005 and recovery of arms and ammunition from Mohan Basumatary, an armed militant of NDFB who was apprehended after a chase.

PW-9, Shri Partha Sarathy Mahanta, Superintendent of Police, Dhubri, Assam stated that the affidavit P-9 dated 6-2-2007 was deposed to by him. He proved Ex. PW-9/1, Ex. PW-9/2, Ex. PW-9/3(1) to Ex. PW-9/3(6), Ex. PW-9/4(1) to Ex. PW-9/4(3), Ex. PW-9/5(1), Ex. PW-9/5(2), Ex. PW-9/5(3) to Ex. PW-9/5(4), Ex. PW-9/6(1) to Ex. PW-9/6(4). The originals were seen and returned. The documents established extortion by NDFB cadre members and violent incidents resulting in death due to chance presence of the police in the market where local shopkeepers were being threatened. The documents established, through the statements of relatives of the deceased extortionists that they were recruited as NDFB cadre members. He stated that offending activities of NDFB cadre in his district were mainly directed against non-Boro citizens.

PW-10, Shri Pankaj Sharma, Superintendent of Police, Udalguri District, Assam stated that the affidavit P-10 dated 8-2-2007 was deposed to by him. He proved documents Ex. PW-10/1, Ex. PW-10/1(1), Ex. PW-10/2, Ex. PW-10/3, Ex. PW-10/3(1), Ex. PW-10/4, Ex. PW-10/4(1), Ex. PW-10/5(1) to Ex. PW-10/5(7) and Ex. PW-10/6(1) Ex. PW-10/6(3). Originals were seen and returned. The documents establish recovery of arms and ammunitions from NDFB cadre members. They consisted of statements of arrested NDFB cadre members admitting their involvement. The documents are FIRs pertaining to kidnapping of persons by NDFB cadre members. He stated that the incidents of extortion, kidnapping, murder and explosions detailed in Ex. PW-1/3, in his district were directed against non-Boro citizens. The witness stated that pursuant to FIR, Ex. PW-10/4 further investigation reveal that 5 personnel of Shashtra Sewa Bal namely Ct. P. Robi Singh, Ct. H. Lakshab Singh, Ct. Thenghalica Vaiphai, Ct. Amongba Sangtham and Ct. Cook Krishna Bahadur Chetri were kidnapped along with one Bubul Kalita. All of whom were found killed and bodies recovered from the foothills of Belshir, adjacent to Assam Arunachal border. He further stated that the of-

fending vehicles in which the kidnapped persons were transported was recovered. Bhikaraja, Halia and Gala all of whom were NDFB activists were involved.

PW-11, Satyendra Narayan Singh, Senior Superintendent of Police, Guwahati City, Assam stated that the affidavit P-JJ dated 10-2-2007 was deposed to by him. He proved documents Ex. PW-11/1, Ex. PW-11/2, Ex. PW-11/3, Ex. PW 11/3(1) and Ex. PW-11/4. Originals were seen and returned. In addition to the documents filed, he produced a diary seized from a NDFB cadre member wherein names of 18 cadre members engaged in extortion were listed. Expenditure incurred from 11-7-2004 to 23-9-2004 on NDFB cadre members who were sent to different places to collect extortion money was recorded therein. The documents proved by the witness were extortion letters written by NDFB members to different persons.

Ex. PW-11/4 was a letter recovered by the State intelligence. It has been addressed by one B. Sudem and B. Jaiklong styled as Command-NDFB. It is addressed to D.C. Dashu in Bhutan. The letter states that Boro race is of Bhutanese Mongoloid origin. The letter seeks cooperation from Bhutanese people.

PW-12, Shri M.P. Gupta, Superintendent of Police, Sonitpur District, Assam stated that affidavit P-12 dated 7-2-2007 was deposed to by him. He proved documents Ex. PW-12/1, Ex. PW-12/2(1), Ex. PW-12/2(2), Ex. PW-12/2(3), Ex. PW-12/2(4), Ex. PW-12/3, Ex. PW-12/4(1), Ex. PW-12/4(2) and Ex. PW-12/4(3). Originals were seen and returned. The documents proved by the witness evidence recovery of arms and ammunitions, mobile telephones, cash and other incriminating documents. The documents are statements of arrested NDFB militants admitting their involvement and recovery of arms. The documents are money receipts evidencing collection of extortion money.

PW-13, R.R. Jha, Director of the Government of India, Ministry of Home Affairs stated that the affidavit P-13 was deposed to by him as per information received and forwarded to him from various Central Agencies and the State Government. He stated that the names of office bearers of NDFB disclosed in Annexure-1 to the report were as per intelligence reports received. Similarly, information in said annexure pertaining to links of NDFB with other secessionist organizations operating in the North East and other foreign links were as per intelligence report. On being asked whether witness could produce a few intelligence reports, the witness responded in the affirmative and produced a few reports received by Ministry of Home Affairs from I. B., Director General, CRPF (Operation Branch), R.A.W. and Government of Assam. Major incidents of violence committed by NDFB members detailed in Annexure-2 to the affidavit were stated to be based on a report submitted by the Intelligence Bureau on 24-7-2006. Photocopy of the report was tendered. (It was perused and kept in a sealed cover). He stated that even Government officials were being targeted by NDFB cadre and even Boro citizens who were opposed to ideology of NDFB were being harassed.

The evidence on record establishes that the ideology of NDFB as per its Constitution to undermine the integrity and sovereignty of India by waging an armed struggle and establish Boroland is still being propagated through violent means. Notwithstanding the accord obliging NDFB to suspend activities, offending activities are continuing. Evidence establishes 76 incidents involving use of violence. Extortion attempts and extortions actually carried out show money being collected to carry forward the violent activities. Ex. PW-11/4 shows an attempt to seek patronage from external authorities across the border. Evidence on record establishes that 13 district in the State of Assam are affected.

NDFB was declared an Unlawful Association way back on 23-11-1992 and notwithstanding successive notifications declaring it to be a continuing unlawful association, offending activities have continued.

For the evaluation of the evidence as noted above, two things have to be kept in mind. For the purposes of adjudication by the Tribunal whether the statement recorded under Section 161 Cr. P.C. can be taken into consideration by the Tribunal or not.

In Union of India Vs. Students Islamic Movement of India & Ors., 99 (2002) DLT 147, the Delhi High Court observed :—

"The confessional statements referred to and relied upon by the Government, were recorded during investigation of the criminal cases in which they were arrested. Section 25 of the Evidence Act provides that no confession made to a police officer shall be proved against a person accused of any offence. The expression 'a person accused of an offence' describes the person against whom evidence is sought to be proved in a criminal case. The adjective clause 'accused of an offence', is therefore, descriptive of the person against whom a confession is sought to be proved. The confessional statements, can be used in civil proceedings and other collateral proceedings under the Criminal Procedure Code. The inquiry before this Tribunal is clearly not a trial against the accused persons, who made the confessional statements. Therefore, in my considered view confessional statements made by the accused persons during investigation of different cases to the police or before the Court, would not be hit by Section 25 of the Evidence Act and are admissible in evidence, to show whether the accused persons were or are the members of the association, as well as to show whether the activities of the association are unlawful or not."

In Suman & Ors. Vs. State of Tamil Nadu, AIR 1986 (Madras) 318, it was held :

"It has to be remembered that when Section 25 refers to a confession which is not permitted to be proved as against a person accused of any offence, it refers to a confession made by an accused person which is

proposed to be proved against him to establish an offence. The scope of Section 25 is therefore restricted only to a confession made by a person who is an accused that is being used in a proceeding to establish an offence against him."

As to what is the material and how the same has to be considered by the Tribunal has been laid down by the Supreme Court in *Jamat-E-Islami Hind Vs. Union of India*, JT 1995 (1) SC 31. Supreme Court held as under :

"Section 4 deals with reference to the Tribunal, sub-section (1) requires the Central Government to refer the notification issued under sub-section (1) of Section 3 to the Tribunal "for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the association unlawful". The purpose of making the reference to the Tribunal is an adjudication by the Tribunal of the existence of sufficient cause for making the declaration. The words "adjudicating" and "sufficient cause" in the context are of significance. Sub-section (2) requires the Tribunal, on receipt of the reference, to call upon the association affected 'by notice in writing to show cause' why the association should not be declared unlawful. This requirement would be meaningless unless there is effective notice of the basis on which the declaration is made and a reasonable opportunity to show cause against the same. Sub-section (3) prescribes an inquiry by the Tribunal, in the manner specified, after considering the cause shown to the said notice. The Tribunal may also call for such other information as it may consider necessary from the Central Government or the association to decide whether or not there is sufficient cause for declaring the association to be unlawful. The Tribunal is required to make an order which it may deem fit "either confirming the declaration made in the notification or cancelling the same". The nature of inquiry contemplated by the Tribunal requires it to weigh the material on which the notification under sub-section (1) of Section 3 is issued by the Central Government, the cause shown by the association in reply to the notice issued to it and take into consideration such further information which it may call for, to decide the existence of sufficient cause for declaring the association to be unlawful. The entire procedure contemplates an objective determination made on the basis of material placed before the Tribunal by the two sides; and the inquiry is in the nature of adjudication of a lis between two parties, the outcome of which depends on the weight of the material produced by them. Credibility of the material should, ordinarily, be capable of objective assessment. The decision to be made by the Tribunal is "whether or not there is sufficient cause for declaring the association unlawful". Such a determination requires the Tribunal to reach the conclusion that the material to support the declaration outweighs the material against it and the additional weight to support the declaration is sufficient to sustain it. The test of greater probability appears to be the pragmatic test applicable in the context."

Supreme Court in para 14 further held that :—

"In Section 4, the words "adjudicating" and "decide" have a legal connotation in the context of the inquiry made by the Tribunal constituted by a sitting Judge of a High Court. The Tribunal is required to 'decide' after 'notice to show cause' by the process of 'adjudicating' the points in controversy. There are the essential attributes of a judicial decision."

(Emphasis supplied)

In *Union of India vs. Tulsiram Patel*, AIR 1985 SC 1416, a Constitution Bench of the Court had the occasion of considering the expressions "law and order", "public order", "Security of the State", which are used in different Acts. In para 140 of the judgment, their Lordships observed as under :

"The expression 'law and order', 'public order' and 'security of the State' have been used in different Acts. Situations which affect "public order" are graver than those which affect "law and order" and situations which affect "security of the State" are graver than those which affect "public order". Thus, of those situations those which affect "security of the State" are the gravest. Danger to the security of the State may arise from without or within the State. The expression "security of the State" does not mean security of the entire country or a whole State. It includes security of a part of the State. It also cannot be confined to an armed rebellion or revolt. There are various ways in which security of the State can be affected. It can be affected by the State secrets or information relating to defence production or similar matters being passed on to the other countries, whether inimical or not to our country, or by secret links with terrorists. It is difficult to enumerate the various ways in which security of the State can be affected. The way in which security of the State is affected may be either open or clandestine."

Applying the above tests and considering the material placed on record I am of the considered opinion that the material placed before the Tribunal was credible and being not impeached has to be accepted. Therefore, the Tribunal is satisfied that the activities of NDFB, its members, followers and sympathizers are subversive in nature. Their activities are secessionist and against the territorial integrity and sovereignty of India. Therefore, there is sufficient cause for declaring NDFB 'Unlawful Association' pursuant to the notification dated 23-11-2006 and the said notification stands confirmed. The reference stands answered in the terms mentioned above.

May 14, 2007

PRADEEP NANDRAJOG, J. Unlawful Activities
(Prevention) Tribunal

[No. 11011/48/2006-NE. III]

NAVEEN VERMA, Jt. Secy.